सुब्रमण्यन

बनाम

तमिलनाडु राज्य और एक अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 417/2012)

21 फरवरी, 2012

[पी. सदाशिवम और जे. चेलमेश्वर, न्यायाधिपतिगण]

निवारक निरोध:

तमिलनाडु की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम (शराब की तस्करी, ड्रग अपराधी, वन अपराधी, गुंडा, अनैतिक तस्करी अपराधी, रेत अपराधी, स्लम ग्रैबर्स और वीडियो समुद्री डाकू अधिनियम, 1982 – धारा 3 और 2 (1) - धारा 3 के तहत निरोध आदेश , बंदी के खिलाफ - बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका - उच्च न्यायालय द्वारा खारिज - अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: निरोध में लेने वाले प्राधिकारी ने रखी गई सामग्रियों पर विचार करने पर पाया कि बंदी आदतन अपराध कर रहा है और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से कार्य कर रहा है और इस प्रकार वह एक 'गुंडा' है जैसा कि धारा 2 (एफ) के तहत माना जाता है - 'अरुवल' से लैस बंदी अपने साथियों के साथ 'कट्टा' से लैस होकर शिकायतकर्ता की दुकान पर आए, उसे धमकी दी और दुकान में उपलब्ध संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया - यह नहीं कहा जा सकता है कि निरोध में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक सामग्री पर दिमाग का उपयोग नहीं किया गया था; और निरोध में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा निरोध में लिए गए प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया गया था जो पूरे निरोध आदेश को रद्द कर देता है - निरोध में लेने वाले प्राधिकारी का यह निष्कर्ष कि निरोध में लिया गया व्यक्ति आदतन अपराधी था, पुराने उदाहरणों के आधार पर नहीं माना जा सकता है - निरोध के आधार

में उल्लिखित सभी घटनाएं स्पष्ट रूप से निरोध में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की गई व्यक्तिपरक संतुष्टि को प्रमाणित करती हैं कि निरोध में लिए गए लोगों के कार्य निरोध में लिए गए लोग सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल कैसे हुए थे - इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने निरोध के आदेश को सही ठहराया।

मौजूदा मामले में, जमीनी मामले की घटना बंदी और शिकायतकर्ता के बीच भूमि विवाद से उत्पन्न हुई। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि अरुवल (दरांती) से लैस बंदी ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को धमकाने के अलावा एसटीडी बूथ को नुकसान पहुंचाया। उक्त घटना से पहले बंदी वर्ष 2008 और 2010 के मामलों में शामिल था। प्रतिवादी नंबर 2-पुलिस आयुक्त ने तमिलनाडु में बूटलेगर्स, ड्रग अपराधियों की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम की धारा 3 के तहत निरोध में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ निरोध का आदेश पारित किया था। वन अपराधी, गुंडा, अनैतिक व्यापार अपराधी, रेत अपराधी, स्लम ग्रैबर्स और वीडियो समुद्री डाकू अधिनियम, 1982 के तहत उक्त मामले के साथ-साथ पिछले मामलों में भी उसकी संलिप्तता को देखते हुए उसे गुंडा माना गया है। अपीलकर्ता ने एक अभ्यावेदन दायर किया और उसे अस्वीकार कर दिया गया। व्यथित होकर, अपीलकर्ता (निरोध में लिए गए व्यक्ति के पिता) ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया। इसलिए, अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए, अभिनिर्धारित किया :

1.1 असाधारण और अत्यंत सीमित आधारों को छोड़कर अदालत निरोध प्राधिकारी द्वारा प्राप्त व्यक्तिपरक संतुष्टि में हस्तक्षेप नहीं करती है। जब निरोध के आधार सटीक, प्रासंगिक, निकटवर्ती और प्रासंगिक हों तो अदालत निरोध में लेने वाले प्राधिकारी की राय के स्थान पर अपनी राय नहीं रख सकती है, कि आधार की पर्याप्तता अदालत के

लिए नहीं है, बल्कि व्यक्तिपरक संतुष्टि के गठन के लिए निरोध में लेने वाले प्राधिकारी के लिए है। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से यह आवश्यक है और ऐसी संतुष्टि व्यक्तिपरक है न कि वस्तुनिष्ठ। निवारक निरोध के कानून का उद्देश्य दंडात्मक नहीं है, बल्कि केवल निवारक है और इसके अलावा किसी व्यक्ति को निरोध में लेने में कार्यपालिका की कार्रवाई केवल एहतियाती होने के कारण, आम तौर पर मामले को कार्यकारी प्राधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। आचरण के वस्तुनिष्ठ नियमो को विस्तृत तरीके से निर्धारित करना व्यवहारिक नहीं है। इसलिए, निरोध में लेने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि को उसके विवेक के प्रयोग में कुछ अक्षांशों के साथ प्राथमिक महत्व माना जाता है। [पैरा 11] [996-बी-ई]

1.2 निरोध प्राधिकारी ने रखी गई सामग्रियों पर विचार करने पर पाया कि आरोपियों ने सार्वजनिक और निजी दोनों संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, जनता को धमकी दी और जनता के बीच दहशत की स्थिति भी पैदा की। निरोध में लेने वाले प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट थे कि बंदी आदतन अपराध कर रहा है और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से काम कर रहा है और इस तरह वह एक 'गुंडा' है, जैसा कि तमिलनाडु शराब के तस्कर, ड्रग अपराधी, वन अपराधी, गुंडा, अनैतिक व्यापार अपराधी, रेत अपराधी, स्लम ग्रैबर्स और वीडियो समुद्री डाकू की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1982 की धारा 2 (एफ) के तहत माना गया है। निरोध प्राधिकरण ने यह भी पाया कि उसे इस तरह के गतिविधियो में भविष्य में शामिल होने से रोकने के लिए उसे निरोध में लेने की अनिवार्य आवश्यकता है, जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल हों। [पैरा 9-10] [994-डी-एफ; 995-ई-एफ]

1.3 बंदी, 'अरुवल' से लैस होकर, अपने साथियों के साथ, 'कट्टा' से लैस होकर शिकायतकर्ता के स्थान पर आया। बंदी ने शिकायतकर्ता को गंदी भाषा में गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। उसके साथियों ने भी उसे धमकाया। बंदी ने न केवल शिकायतकर्ता को 'अरुवल' जैसे हथियार से धमकाया, बल्कि दुकान में उपलब्ध संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। जब शिकायतकर्ता ने बंदी और उसके साथियों से पूछताछ की तो बंदी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। जब परिवादी ने बचाव के लिए शोर मचाया तो आसपास की आम जनता के आ जाने पर बंदी व उसके सहयोगियों द्वारा उन्हें भी धमकी दी गयी कि वे उन्हें जान से मार देंगे, निरोध के आधारों से यह भी पता चलता है कि बंदी और उसके साथियों द्वारा हथियार दिखाकर धमकाने के कारण आसपास के दुकानदारों ने डर के मारे अपनी दुकानें बंद कर दीं और ऑटो चालक अपने स्टैंड से ऑटो लेकर वहां से चले गये. निरोध प्राधिकारी के अनुसार, उपरोक्त दृश्य ने जनता के बीच दहशत पैदा कर दी। ऐसी परिस्थितियों में, बंदी और उसके सहयोगियों द्वारा बनाए गए दृश्य को केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं कहा जा सकता है, बल्कि यह सार्वजनिक व्यवस्था है, जैसा कि निरोध में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया गया है, जिसे जनता के हितों की रक्षा और संरक्षण करना चाहिए। [पैरा 13] [997-बी-एफ]

1.4 यह दलील तथ्यात्मक रूप से गलत है कि आरोपी ने निरोध आदेश में संदर्भित सभी आपराधिक मामलों में नियमित जमानत प्राप्त की थी, न कि अग्रिम जमानत, और इस प्रकार, निरोध में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक सामग्री पर दिमाग का उपयोग नहीं किया गया है। उक्त निवेदन बाद में इस न्यायालय के समक्ष अभी किया गया था। उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष एकमात्र तर्क यह था कि निरोध में लिए गए व्यक्ति को 2010 के अपराध संख्या 727 में नियमित जमानत मिली थी, लेकिन निरोध में लेने वाले

प्राधिकरण ने इसे अग्रिम जमानत के रूप में गलत तरीके से उल्लेख किया था। इसके अलावा, एसएलपी में कोई विशेष आधार नहीं उठाया गया था। एकमात्र आधार यह है कि अपराध संख्या 727 /2010 में अग्रिम जमानत आदेश की प्रति बंदी को नहीं दी गई थी, जो रिकॉर्ड के विपरीत भी है क्योंकि निरोध आदेश में विशेष रूप से ऐसा कहा गया है और जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि सभी बंदी को सामग्री विधिवत प्रदान की गई। प्रत्युत्तर दाखिल करने से इसका खंडन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, निरोध में लिए गए व्यक्ति ने अपराध संख्या 727 /2010 सहित निरोध आदेश में संदर्भित मामलों में अग्रिम जमानत प्राप्त कर ली थी। [पैरा 14] [997-जी-एच; 998-ए-सी][

1.5 उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बंदी को जमानत या अग्रिम जमानत दी जाना कोई मायने नहीं रखता, जहां तक तथ्य यह है कि वह उन मामलों में रिमांड पर नहीं था और निरोध आदेश में किए गए संदर्भ के कारण निरोध में लिए गए व्यक्ति पर कोई पूर्वाग्रह नहीं था। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि जमीनी मामले के संबंध में जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश, स्थान 'टी' के समक्ष लंबित थी और उसे जमानत पर रिहा किए जाने की बहुत संभावना थी और यदि वह जमानत पर बाहर आया, तो वह भविष्य में ऐसी गतिविधियो में लिप्त हो जाएगा जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल होंगी। [पैरा 15] [998-ई-एफ]

1.6 यह दलील कि निरोध में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा बंदी के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया, जो पूरे नजरबंदी आदेश को रद्द कर देता है, पूरी तरह से निराधार है क्योंकि बंदी ने एक साथ सरकार को अभ्यावेदन दिया था और सरकार ने उसके अभ्यावेदन पर पूरी तरह से विचार किया था और उसे दिनांक 12.08.2011 को खारिज कर दिया था। सलाहकार बोर्ड ने भी दिनांक 23.08.2011 के आदेश द्वारा बंदी

के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया, जिससे निरोध की पुष्टि हुई। [पैरा 16] [998-जी-एच; 999-ए-डी]

श्री आनंद हनुमत्सा कटारे बनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य 2006 (10) एससीसी 725: 2006 (7) पूरक एससीआर 622 का संदर्भ दिया गया।

1.7 जमीनी मामला दिनांक 18.07.2011 की घटना से संबंधित है और उससे पहले, बंदी वर्ष 2010 में दो मामलों में और वर्ष 2008 में एक मामले में शामिल था। उपरोक्त विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बंदी एक आदतन अपराधी था और जैसा कि दिखाए गए ऐसे उदाहरण पुराने नहीं हैं। इन पहलुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान दिया गया, वास्तव में, उच्च न्यायालय ने पाया कि बंदी वर्ष 2008 में एक मामले में और वर्ष 2010 में दो मामलों में और 2011 में जमीनी मामले में शामिल था। विवरण यह भी दर्शाता है कि वर्ष 2010 में, बंदी 6 महीने की अवधि के भीतर दो मामलों में शामिल हो गया था और वर्ष 2011 में फिर से जमीनी मामले में शामिल हो गया था, इसलिए घटना संख्या 2 और 3 को पुरानी नहीं कहा जा सकता और ऐसी परिस्थिति में, निरोध में लेने वाले प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि निरोध में लिया गया व्यक्ति आदतन अपराधी था, इसे पुराने उदाहरणों पर आधारित नहीं माना जा सकता है। [पैरा 17] [999-ई-एच]

1.8 घटनाओं को निरोध के आधार पर उजागर किया गया था, साथ ही उसके प्रभाव के बारे में निश्चित संकेत दिए गए थे, जो निरोध के आधार में सटीक रूप से बताए गए थे। निरोध के आधार में उल्लिखित सभी घटनाएं स्पष्ट रूप से निरोध प्राधिकारी द्वारा प्राप्त व्यक्तिपरक संतुष्टि को प्रमाणित करती हैं कि कैसे बंदी के कार्य सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल थे। इन सभी पहलुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा

विचार किया गया जिसने निरोध के आदेश की सही पुष्टि की। [पैरा 18, 19 और 20] [1000-ए-ई]

पुलिस आयुक्त एवं अन्य बनाम सी. अनीता (श्रीमती) 2004 (7)एससीसी 467: 2004 (3) पूरक एससीआर 701; भारत संघ बनाम पॉल मनिकम एवं अन्य (2003) 8 एससीसी 342: 2003 (4) पूरक एससीआर 618; एम. अहमदकुट्टी बनाम भारत संघ और अन्य (1990) 2 एससीसी 1: 1990 (1) एससीआर 209 – अंतर स्पष्ट किया।

पुष्पा देवी एम. जटिया बनाम एम.एल. वधावन और अन्य 1987 (3) एससीसी 367: 1987 (3) एससीआर 46; राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य (1966) 1 एससीआर 709; भारत संघ बनाम अरविंद शेरगिल और अन्य 2000 (7) एससीसी 601; सुनील फूलचंद शाह बनाम भारत संघ एवं अन्य 2000 (3) एससीसी 409: 2000 (1) एससीआर 945 - पर भरोसा व्यक्त किया।

केस कानून संदर्भ:

1987 (3) एससीआर 46	भरोसा व्यक्त किया	पैरा 12
(1966) 1 एससीआर 709	भरोसा व्यक्त किया	पैरा 12
2000 (7) एससीसी 601	भरोसा व्यक्त किया	पैरा 12
2000 (1) एससीआर 945	भरोसा व्यक्त किया	पैरा 12
2006 (7) पूरक एससीआर 622	संदर्भ दिया गया	पैरा 16
2004 (3) पूरक एससीआर 701	अंतर स्पष्ट किया	पैरा 18
2003 (4) पूरक एससीआर 618	अंतर स्पष्ट किया	पैरा 18
1990 (1) एससीआर 209	अंतर स्पष्ट किया	पैरा 18

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 417/2012

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 937 /20211 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 9.12.2011 से।

ए शरण, आशुतोष झा, विवेक सिंह, असीम चंद्रा, अमित आनंद तिवारी, अपीलकर्ता की ओर से।

गुरु कृष्ण कुमार, एएजी, प्रसन्ना वेंकट, बी. बालाजी, प्रतिवादीगण के लिए।

न्यायालय का निर्णय पी. सदाशिवम, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया। अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 937 /2011 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 09.12.2011 के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।

3. संक्षिप्त तथ्य:

(ए) अपीलकर्ता बंदी का पिता है। निरोध में लिए गए लोगों का कालियामूर्ति नाम के व्यक्ति के साथ अपनी जमीन को लेकर विवाद है, जिसके लिए एक सिविल सूट ओ.एस. नंबर 452/2008 त्रिची में अधीनस्थ न्यायाधीश के समक्ष लंबित है। उक्त कल्यामूर्ति ने 18.07.2011 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि अरुवल (दराती) से लैस बंदी ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता कलियामूर्ति को धमकाने के अलावा एसटीडी बूथ के शीशे और कुर्सियों को नुकसान पहुंचाया। तदनुसार, एफआईआर संख्या 361 /2011 के.के. नगर पुलिस स्टेशन, त्रिची द्वारा दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता - कालियामूर्ति ने पहले ही 07.02.2010 को सिटी क्राइम ब्रांच, त्रिची के

समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे पुलिस ने प्रकरण अपराध नंबर 3/2010 के रूप में दर्ज किया था जो अभी भी लंबित है।

(बी) 21.07.2011 को, प्रतिवादी नंबर 2 पुलिस आयुक्त ने तमिलनाडु की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम (शराब की तस्करी, ड्रग अपराधी, वन अपराधी, गुंडा, अनैतिक तस्करी अपराधी, रेत अपराधी, स्लम ग्रैबर्स और वीडियो समुद्री डाकू अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 3 के तहत निरोध में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ बंदी को 18.07.2011 के मामले के साथ-साथ वर्ष 2008 और 2010 के तीन पिछले मामलों में उसकी संलिप्तता को देखते हुए 'गुंडा' करार देते हुये निरोध का आदेश पारित किया गया।

(सी) हिरासत के उक्त आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ता ने हिरासत आदेश को रद्द करने के लिए 25.07.2011 को हिरासत प्राधिकरण को एक अभ्यावेदन भेजा। उन्होंने उक्त आदेश के खिलाफ राज्य सरकार, जो अनुमोदन प्राधिकारी है, को एक अभ्यावेदन भी दिया। 28.07.2011 को अपीलकर्ता का अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद, हिरासत प्राधिकारी ने इसे अस्वीकार करने की सिफारिश करते हुए इसे सरकार को भेज दिया। दिनांक 12.08.2011 को राज्य सरकार ने विचारोपरान्त उक्त अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया।

(डी) राज्य सरकार के उक्त निर्णय से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 09.12.2011 को अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा उक्त याचिका को खारिज कर दिया।

(ई) उच्च न्यायालय के उक्त फैसले को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ए. शरण और प्रतिवादीगण के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री गुरु कृष्णकुमार को सुना गया।

5. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ए. शरण ने निरोधक आदेश और उसकी पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के माध्यम से हमें बताया कि रखी गई सामग्रियों से, हिरासत प्राधिकारी ने निवारक के लिए कोई मामला नहीं बनाया है। कैद। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि भले ही हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी का रुख स्वीकार्य हो, हिरासत में लिए गए व्यक्ति की कथित कार्रवाई, अधिक से अधिक, केवल कानून और व्यवस्था की समस्या है, न कि सार्वजनिक व्यवस्था की, जैसा कि उक्त प्राधिकारी ने टी.एन. 1982 का अधिनियम 14 लागू करने के लिए किया था। उन्होंने आगे कहा कि हिरासत प्राधिकारी द्वारा हिरासत के आधार पर तीनों स्थानों पर यह संदर्भ दिया गया कि आरोपी ने नियमित जमानत प्राप्त की है और अग्रिम जमानत नहीं, प्राधिकारी द्वारा दिमाग का गैर-प्रयोग दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की ओर से हिरासत में लिए गए लोगों के प्रतिनिधित्व पर विचार करने में विफलता पूरे आदेश को रद्द कर देती है। अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि हिरासत प्राधिकारी द्वारा जिन मामलों पर भरोसा किया गया है वे पुराने हैं और टी.एन. 1982 का अधिनियम 14 के प्रावधानों को लागू करने का कोई आधार नहीं है।

6. दूसरी ओर, तमिलनाडु राज्य के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री गुरु कृष्णकुमार ने हमें हिरासत के आधार, इसकी पुष्टि करने में उच्च न्यायालय के तर्क और काउंटर के रूप में रखी गई सामग्री के बारे में जानकारी दी। इस न्यायालय के समक्ष हलफनामे में कहा गया कि हिरासत में लिए गए वरिष्ठ वकील द्वारा दी गई कोई भी दलील स्वीकार्य नहीं है और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

7. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने से पहले, टी.एन. 1982 का अधिनियम 14 में वर्णित 'गुंडा' की परिभाषा का उल्लेख करना प्रासंगिक है। जो इस प्रकार है:

> 2(1) "गुंडा" का अर्थ है वह व्यक्ति, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम XLV) के अध्याय VIII या अध्याय XVI या अध्याय XVII या अध्याय XXII की धारा 153 या धारा 153-ए के अंतर्गत दंडनीय या तमिलनाडु संपत्ति (क्षति और हानि की रोकथाम) अधिनियम, 1992 (1992 का तमिलनाडु अधिनियम 59) की धारा 3 या धारा 4 या धारा 5 के तहत दंडनीय, स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या नेता के रूप में, आदतन करता है, या करने का प्रयास करता है या अपराध कारित करने के लिये उकसाता है

उक्त अधिनियम राज्य द्वारा वर्ष 1982 में अधिनियमित किया गया था और बाद में कुछ व्यक्तियों को खतरनाक गतिविधियों से रोकने के लिए अधिनियम के दायरे का विस्तार करते हुए संशोधन किया गया, जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक हैं। चूंकि शक्ति और निष्पादन के संबंध में कोई विवाद नहीं है, इसलिए अन्य प्रावधानों को संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

8. हमने सभी प्रासंगिक सामग्रियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

9. पहले निवेदन के संबंध में कि टी.एन. 1982 का अधिनियम 14 के प्रावधानों को लागू करके निवारक हिरासत के लिए कोई मामला नहीं बनता है। यद्यपि जमीनी मामला घटना बंदी और वास्तविक शिकायतकर्ता के बीच भूमि विवाद से उत्पन्न हुई थी, तथापि, यह तर्क कि यह केवल कानून और व्यवस्था की समस्या है और सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं हुई थी, तथ्यों के विपरीत है और समान रूप से अस्थिर है। जैसा कि हिरासत प्राधिकारी श्री गुरु कृष्णकुमार ने ठीक ही बताया है। रखी गई

सामग्रियों पर विचार करने पर पाया गया कि आरोपियों ने सार्वजनिक और निजी दोनों संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, जनता को धमकाया और जनता के बीच दहशत की स्थिति भी पैदा की। इस संबंध में, हिरासत के आधारों में वर्णित सामग्रियों का उल्लेख करना उपयोगी है जो इस प्रकार हैं:

"18.07.2011 को, लगभग 10:00 बजे, जब कालियामूर्ति एसटीडी बूथ, काजामलाई कदैवीथी, काजामलाई, तिरुचिरापल्ली शहर में उपलब्ध थे, आरोपी काजामलाई विजल विजय अरुवल से लैस थे, उनके सहयोगी मणिकंदन, उथयान, साथिया, शिवकुमार जो कि कट्टो से से लैस थे, वहां आए। आरोपी कजामलाई विजी उर्फ विजय ने कालियामूर्ति को गंदी भाषा में गाली दी, उसे अरूवल से जान से मारने के लिये धमकाया यह कहते हुये कि "क्या तुम इतने बड़े आदमी हो गए कि मेरे खिलाफ शिकायत दो" साले, शिकायत देकर देख, यहीं काट डालूँगा तुझे।"

उसके साथियों ने अपने-अपने कट्टे दिखाकर उसे धमकाया।

इसके बाद आरोपी कजमलाई विजी उर्फ विजय ने दुकान में उपलब्ध चश्मे, कुर्सी और स्टूल को नुकसान पहुंचाया। जब कालियामूर्ति ने उनसे प्रश्न किया, तो आरोपी कजामलाई विजी उर्फ विजय ने उनके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। कालियामूर्ति ने बचाव के लिए शोर मचाया। आम जनता वहां आ गई और उन्हें आरोपी काजमलाई विज @ विजय और उसके सहयोगियों ने यह कहकर धमकी दी कि "अगर कोई गवाह के रूप में सामने आया, तो मैं उन्हें मार डालूंगा।" आसपास के दुकानदारों ने डर के मारे अपनी दुकानें बंद कर दीं। ऑटो चालक स्टैंड से अपने ऑटो लेकर वहां से चले गये। इस स्थिति से जनता में दहशत फैल गई। कालियामूर्ति की शिकायत पर के.के. नगर पुलिस थाने में अपराध

क्रमांक 361/2011 अंतर्गत धारा 147, 148, 447, 448, 427, 294(बी), 323, 506(i) आईपीसी और 3 पी.पी.डी. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।"

10. उपरोक्त सामग्रियों से, हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी संतुष्ट था कि बंदी आदतन अपराध कर रहा है और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य कर रहा है और इस तरह वह एक 'गुंडा' है जैसा कि टी.एन. 1982 के अधिनियम 14 की धारा 2 (एफ) के तहत माना गया है। आदेश आगे दर्शाता है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने पाया कि उसे भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए उसे हिरासत में लेने की अनिवार्य आवश्यकता है जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल हैं। जमीनी मामले का विवरण बताने के बाद और वर्ष 2008 और 2010 से शुरू होने वाले पहले के उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, निरोधक प्राधिकारी ने निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला है: -

"इसलिए, मैं संतुष्ट हूं कि आरोपी काजमलाई विजी @ विजय आदतन अपराध कर रहा है और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से काम कर रहा है और इस तरह वह एक गुंडा है जैसा कि तमिलनाडु अधिनियम 1982 का नंबर 14 की धारा 2 (एफ) के तहत माना जाता है। व्यस्त मोहल्ले सह व्यवसायिक क्षेत्र में उपरोक्त वर्णित गंभीर अपराध को अंजाम देकर, उसने उस क्षेत्र के लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा की है जिसमें घटना हुई थी और इस तरह सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य किया।"

11. यह अच्छी तरह से तय है कि अदालत असाधारण और बेहद सीमित आधारों को छोड़कर हिरासत प्राधिकारी द्वारा प्राप्त व्यक्तिपरक संतुष्टि में हस्तक्षेप नहीं करती है। जब हिरासत के आधार सटीक, प्रासंगिक, निकटवर्ती और प्रासंगिक हों तो अदालत हिरासत

में लेने वाले प्राधिकारी की राय के स्थान पर अपनी राय नहीं रख सकती है, कि आधार की पर्याप्तता अदालत के लिए नहीं है, बल्कि व्यक्तिपरक संतुष्टि के गठन के लिए हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के लिए है। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से यह आवश्यक है और ऐसी संतुष्टि व्यक्तिपरक है न कि वस्तुनिष्ठ। निवारक हिरासत के कानून का उद्देश्य दंडात्मक नहीं बल्कि केवल निवारक है और इसके अलावा किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने में कार्यपालिका की कार्रवाई केवल एहतियाती है। आम तौर पर, मामले को आवश्यक रूप से कार्यकारी प्राधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। आचरण के उद्देश्यपूर्ण नियमों को विस्तृत तरीके से निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि को उसके विवेक के प्रयोग में कुछ अक्षांशों के साथ प्राथमिक महत्व माना जाता है।

12. बंदी की ओर से अगला तर्क, इस दलील पर हिरासत आदेश पर हमला करना कि 'कानून और व्यवस्था' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के बीच अंतर है, को भी बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि इस न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला में पूरे देश या यहां तक कि एक निर्दिष्ट इलाके को ध्यान में रखते हुए समुदाय के जीवन की सम गति है, उस सार्वजनिक व्यवस्था को मान्यता दी है। [द्वारा - पुष्पा देवी एम. जटिया बनाम एम.एल. वधावन एवं अन्य, 1987 (3) एससीसी 367 पैरा 11 एवं 14; राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य (1966) 1 एससीआर 709; भारत संघ बनाम अरविंद शेरगिल और अन्य। 2000 (7) एससीसी 601 पैरा 4 और 6; सुनील फूलचंद शाह बनाम भारत संघ एवं अन्य। 2000 (3) एससीसी 409 पैरा 28 (संवैधानिक पीठ); पुलिस आयुक्त एवं अन्य बनाम सी. अनीता (श्रीमती), 2004 (7) एससीसी 467 पैरा 5, 7 और 13]।

13. हमने दिनांक 18.07.2011 के जमीनी मामले के संदर्भ में हिरासत प्राधिकारी की चर्चा, विश्लेषण और अंतिम निर्णय पहले ही निकाल लिया है। यह स्पष्ट है कि बंदी 'अरुवल' से लैस होकर अपने साथियों के साथ 'कट्टा' से लैस होकर शिकायतकर्ता के यहां आया था। बंदी ने शिकायतकर्ता को गंदी भाषा में गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। उसके साथियों ने भी उसे धमकाया। बंदी ने न केवल शिकायतकर्ता को 'अरुवल' जैसे हथियार से धमकाया, बल्कि दुकान में उपलब्ध संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। जब शिकायतकर्ता ने बंदी और उसके साथियों से पूछताछ की तो बंदी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। जब परिवादी ने बचाव के लिए शोर मचाया तो आसपास की आम जनता के आ जाने पर बंदी रक्षकव उसके सहयोगियों द्वारा उन्हें भी धमकी दी गयी कि वे उन्हें जान से मार देंगे। हिरासत के आधार पर यह भी देखा जा रहा है कि बंदी और उसके सहयोगियों द्वारा हथियार दिखा कर धमकाने के कारण आसपास के दुकानदारों ने डर के मारे अपनी दुकानें बंद कर दीं और ऑटो चालक अपने स्टैंड से अपनी ऑटो लेकर वहां से चले गये। हिरासत प्राधिकारी के अनुसार, उपरोक्त दृश्य ने जनता के बीच दहशत पैदा कर दी। ऐसी परिस्थितियों में, बंदी और उसके सहयोगियों द्वारा बनाए गए दृश्य को केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं कहा जा सकता है, बल्कि यह सार्वजनिक व्यवस्था है, जैसा कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया गया है, जिसे जनता के हितों की रक्षा और संरक्षण करना चाहिए। तदनुसार, हम अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाए गए विवाद को खारिज करते हैं।

14. अगला विवाद बंदी द्वारा प्राप्त जमानत के संबंध में हिरासत प्राधिकारी द्वारा विवेक का प्रयोग न करने से संबंधित है। विद्वान एएजी ने हिरासत के आधारों और जवाबी हलफनामे में वर्णित तथ्यात्मक विवरणों पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए प्रस्तुत किया कि ऐसा तर्क तथ्यात्मक रूप से गलत है। एक तर्क उठाया गया है कि

आरोपी ने हिरासत आदेश में उल्लिखित सभी आपराधिक मामलों में नियमित जमानत प्राप्त की थी, न कि अग्रिम जमानत, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया था, और इसलिए, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक सामग्री पर दिमाग का गैर-प्रयोग किया गया है। जैसा कि राज्य के विद्वान वकील ने सही बताया है, उक्त दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। हमारे ध्यान में यह भी लाया गया है कि उक्त निवेदन बाद में इस न्यायालय के समक्ष अभी किया गया था। उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष एकमात्र तर्क यह था कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपराध संख्या 727 /2010 में नियमित जमानत मिली थी, लेकिन हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण ने इसे अग्रिम जमानत के रूप में गलत तरीके से उल्लेख किया है। इसके अलावा, एसएलपी में कोई विशेष आधार नहीं उठाया गया है। एकमात्र आधार यह है कि अपराध संख्या 727 /2010 में अग्रिम जमानत आदेश की प्रति बंदी को नहीं दी गई थी, जो रिकॉर्ड के विपरीत भी है क्योंकि हिरासत आदेश में विशेष रूप से ऐसा कहा गया है और जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि सभी बंदी को सामग्री विधिवत प्रदान की गई। प्रत्युत्तर दाखिल करने से इसका खंडन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, यह बताया गया है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने अपराध संख्या 727 /2010 सहित हिरासत आदेश में संदर्भित मामलों में अग्रिम जमानत प्राप्त कर ली थी, तदनुसार, उक्त विवाद भी खारिज होने योग्य है।

15. उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि बंदी को जमानत या अग्रिम जमानत दिए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां तक तथ्य यह है कि वह उन मामलों में रिमांड पर नहीं था और निरोध आदेश में किए गए संदर्भ के कारण बंदी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं था। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि जमीनी मामले के संबंध में जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश, तिरुचिरापल्ली के समक्ष लंबित थी और उसके जमानत पर रिहा होने की बहुत संभावना थी और यदि वह

जमानत पर बाहर आता है, तो वह भविष्य की गतिविधियों में शामिल हो जाएगा जो कि सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के प्रति पूर्वाग्रह हो जायेगा।

16. बंदी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा बंदी के प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया गया, जो पूरे हिरासत आदेश को रद्द कर देता है। हिरासत प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन 28.07.2011 को ही प्राप्त हुआ था। ऐसा बताया गया है कि एक दिन के भीतर, यानी 29.07.2011 को ही, हिरासत आदेश को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। ऐसी परिस्थितियों में हिरासत प्राधिकारी अभ्यावेदन पर विचार नहीं कर सका। इसके अलावा, एक बार जब सरकार हिरासत आदेश की पुष्टि कर देती है, तो हिरासत प्राधिकारी कार्यात्मक अधिकारी बन जाता है। [श्री आनंद हनुमत्सा कटारे बनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य 2006 (10) एससीसी 725 पैरा 9 और 13 - देखें] अन्यथा भी, जैसा कि राज्य के विद्वान वकील ने ठीक ही बताया है, यह तर्क पूरी तरह से निराधार है क्योंकि बंदी ने एक साथ सरकार को एक अभ्यावेदन दिया था और सरकार ने उसके अभ्यावेदन पर पूरी तरह से विचार किया था और 12.08.2011 को उसे खारिज कर दिया था। इसके अलावा, सलाहकार बोर्ड ने भी दिनांक 23.08.2011 के आदेश द्वारा बंदी के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया है, जिससे हिरासत की पुष्टि हुई है। यह इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-राज्य की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में दी गई जानकारी से भी स्पष्ट है।

17. अंत में, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि हिरासत प्राधिकारी द्वारा जिन मामलों पर भरोसा किया गया है वे पुराने हैं। इस तर्क का उत्तर देने के लिए, हमने एक बार फिर हिरासत के सभी आधारों का अध्ययन किया। जमीनी मामला दिनांक 18.07.2011 की घटना से संबंधित है और उससे पहले, बंदी वर्ष 2010 में दो मामलों में और वर्ष 2008 में एक मामले में शामिल था। उपरोक्त विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बंदी आदतन अपराधी था और इस प्रकार जैसा कि अपीलकर्ता के

विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है, दिखाए गए उदाहरण पुराने नहीं हैं। इन पहलुओं पर उच्च न्यायालय ने गौर किया है, दरअसल उच्च न्यायालय ने पाया है कि बंदी वर्ष 2008 में एक मामले में और वर्ष 2010 में दो मामलों में और 2011 में जमीनी मामले में शामिल था। विवरण भी दिखाते हैं वर्ष 2010 में, बंदी 6 महीने के भीतर दो मामलों में शामिल हो गया था और वर्ष 2011 में फिर से जमीनी मामले में शामिल हो गया था, इसलिए घटना नं. 2 और 3 को पुराना नहीं कहा जा सकता है और ऐसी परिस्थिति में, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी का निष्कर्ष कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति आदतन अपराधी था, को पुराने उदाहरणों पर आधारित नहीं माना जा सकता है।

18. घटनाओं को हिरासत के आधारों में उजागर किया गया है और साथ ही उनके प्रभाव के बारे में निश्चित संकेत भी दिए गए हैं, जो ऊपर उल्लिखित हिरासत के आधारों में सटीक रूप से बताए गए हैं। हिरासत के आधार में उल्लिखित सभी घटनाएं स्पष्ट रूप से हिरासत प्राधिकारी द्वारा प्राप्त व्यक्तिपरक संतुष्टि को प्रमाणित करती हैं कि कैसे बंदी के कार्य सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल थे। इन सभी पहलुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया जिसने हिरासत आदेश की सही पुष्टि की।

19. उपरोक्त निष्कर्ष के मद्देनजर, जबकि हिरासत में लिए गए वरिष्ठ वकील, अर्थात् पुलिस आयुक्त (उपरोक्त), भारत संघ बनाम पॉल मनिकम एवं अन्य, (2003) 8 एससीसी 342, एम. अहमदकुट्टी बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1990) 2 एससीसी 1 द्वारा लिए गए निर्णयों में कानून के प्रस्ताव पर कोई झगड़ा नहीं है। विशिष्ट होने के कारण ये लागू नहीं होते हैं, विशेष रूप से, के मद्देनजर आक्षेपित हिरासत आदेश में बताए गए तथ्यात्मक विवरण, हम उन निर्णयों का विस्तार से उल्लेख नहीं कर रहे हैं।

20. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम अपीलकर्ता की ओर से किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, दूसरी ओर, हम उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हैं, परिणामस्वरूप, अपील असफल होती है और उसे खारिज किया जाता है।

एन.जे. अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।